Class Notes बीए भूगोल पार्ट-2, पत्र-III, इकाई-III

भारत में औद्योगिक विकास
Industrial Development in India

बोलेन्द्र कुमार अगम,
सहायक प्राध्यापक भूगोल,
राजा सिंह कॉलेज सिवान

उद्योग आर्थिक विकास का आधार माना जाता है । इससे ना केवल कृषि के आधुनिकीकरण बल्कि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने में भी सहायता मिलती है । औद्योगिक विकास बेरोजगारी व गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है ।

स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक विकास

प्राचीन काल में भारत अपने कुटीर उद्योगों, शिल्पो तथा वाणिज्य के लिए विख्यात था । आधुनिक औद्योगिक युग के आगमन के पूर्व भारत में कुटीर तथा घरेलू उद्योग समुन्नत थे । भारतीय मलमल, सूतीवस्त्र एवं रेशमी वस्त्र, छपे हुए सूतीवस्त्र, कलात्मक वस्तुएं आदि की विश्व में बहुत मांग थी किंतु इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने भारत के परंपरागत हस्तशिल्प के ऊपर कठोर वज्रपात किया । भारत में औपनिवेशिक काल में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया । आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास सन 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र बनाने और 1855 में रिसरा में (प्रथम जूट मिल कोलकाता के निकट) जूट कारखाने को स्थापित करके किया गया । 1874 ई में कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया । वर्ष 1907 में जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना से औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली ।

स्वतंत्रता पश्चात औद्योगिक विकास

6 अप्रैल 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई । निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करने वाले इस पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई ।

इसके पश्चात समाजवादी आर्थिक विकास के स्थापना के उद्देश्य से प्रथम औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई । इसके अंतर्गत उद्योगों को सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया और अवशिष्ट उद्योगों को निजी उद्यम के लिए खुला छोड़ दिया गया । बाद में समय-समय पर पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर, नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही किंतु इन सब का आधार 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ही रहा ।

पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में वृद्धि

क्रम सं	योजना अवधि	उद्योग क्षेत्र में वृद्धि %
1	पहली योजना	5.54
2	दूसरी योजना	5.59
3	तीसरी योजना	6.28
4	तीन वार्षिक योजनाए	1.42
5	चौथी योजना	4.91
6	पांचवी योजना	6.55
7	छठी योजना	5.32
8	सातवी योजना	6.77
9	दो वार्षिक योजनाए	.10
10	आठवीं योजना	7.58
11	नौवीं योजना	4.29
12	दसवीं योजना	9.17
13	ग्यारहवीं योजना	7.3
14	बारहवीं योजना	9.6

24 जुलाई 1991 में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण नीति की घोषणा की । औद्योगिक विकास की धीमी प्रगति, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता, महंगाई की उच्च दर व विदेशी मुद्रा विनिमय के संकट के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक नीति में एक क्रांतिकारी उद्भव था ।
इस औद्योगिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

1. अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना
2. इसकी विकृति तथा कमियों को दूर करना
3. उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में सुपोषित वृद्धि को बनाए रखना
4. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना

इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय

1. औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन
2. विदेशी तकनीकी का निशुल्क प्रवेश
3. विदेशी निवेश नीति
4. पूंजी बाजार में पहुंच
5. खुला व्यापार
6. प्रावस्थबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन
7. औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण

इस औद्योगिक निवेश के तीन प्रमुख लक्ष्य L P G थे:

उदारीकरण (Liberalization)
निजीकरण (Privatization) और
वैश्वीकरण (Globalization)

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई । साथ ही वर्ष 1956 से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 4 रह गई । संपत्ति देहली की सीमा समाप्त कर दी गई और बिना लाइसेंस क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई । उन्हें केवल निर्धारित प्रारूप में दिए गए विवरण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है । नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है । FDI घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंध कुशलता और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा लाभ प्रदान करता है । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ तथा सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग पर पहुंच की सहमति दे दी । औद्योगिक नीति में घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई गई । क्षेत्र जैसे राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया । इन सभी छूटों के बाद भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आशाओं के अनुकूल नहीं था । स्वीकृत और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बहुत अंतर था । ऐसी सहयोग की संख्या बढ़ रही है ।

वैश्वीकरण: वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान-प्रदान ही वैश्वीकरण है । भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियां वैश्वीकरण से समन्वय स्थापित करने में लगी हुई है । इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व व्यवस्था से जोड़ना है ।

निजीकरण: देश के अधिकतर उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है । इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो जाता है ।

उदारीकरण: इसका उद्देश्य उद्योग और व्यापार को लालफीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है । इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंक, बीमा और जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपए को पूर्ण परिवर्तनशील करना है । इनउद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है ।

GDP में उद्योग क्षेत्र का योगदान

वर्ष	योगदान % में
1950-51	16.6
1960-61	20.5
1970-71	24.0
1980-81	25.9
1990-91	27.7
2000-01	27.3
2010-11	27.8
2011-12	27.5
2012-13	27.3
2013-14	26.1
2016-17	29.02

योजना अवधि में पूंजीगत भारी उद्योगों में निवेश का विस्तार किया गया है जिसके परिणामस्वरुप इंजीनियरिंग वस्तुओं, खनन, लोहा, इस्पात, उर्वरक जैसे उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकी है । औद्योगिक प्रगति के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात प्रतिस्थापन की नीति को सफलतापूर्वक अपनाया जा सका है । भारत के निर्यात में गैर परंपरागत वस्तुओं विशेषकर इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात तेजी से बढ़ा है । इसके परिणामस्वरूप देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को पक्ष में करने में सहायता मिली है । औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवा का विस्तार हुआ है जिससे ना केवल औद्योगिक विस्तार को गति मिली है बल्कि विदेशी मुद्रा को भी बचाया जा सका है । योजना अवधि में औद्योगिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक संरचना में विविधता एवं आधुनिकीकरण देखने को मिलता है । आधारभूत उद्योगों के विस्तार के साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं, औषधि, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भारत के औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है । इसके परिणामस्वरुप भारत के विदेशी व्यापार की संरचना भी अनुकूल हुई है । योजनावधि में हुए औद्योगिक विकास के कारण अब भारत में विनिर्मित वस्तुओं का आयात ना होकर कच्चे माल एवं पूंजीगत पदार्थों का आयात होने लगा है ।

भारत की विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 1.6% से अधिक थी जो 297 बिलियन डॉलर से अधिक था । वर्तमान में भारत विश्व का 19वा अग्रणी पण्य निर्यातक और 13वा अग्रणी पण्य आयातक देश बन गया है । वर्तमान में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन गया है । ध्येय है कि भारतने आयत और निर्यात दोनों में अपना रैंक बढ़ा लिया है । वर्ष 2020 तक विश्व व्यापार में भारत के हिस्सेदारी का लक्ष्य दोगुना रखा गया है ।

भारत में स्थापित विभिन्न उद्योग को स्थापना वर्ष के अनुसार देखने पर भारत का औद्योगिक विकास स्पष्ट दिखाई देता है ।

<u>भारत की महारत्न कंपनियां</u>

1. आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन 1956
2. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964
3. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड 1964

4. स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड 1973
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 1974
6. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन 1975
7. कोल इंडिया लिमिटेड 1975
8. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 1977
9. गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड 1984
10. पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड 1989

<u>नवरत्न कंपनियां</u>

1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 1946
2. भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1954
3. नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड आयल इंडिया लिमिटेड 1956
4. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958
5. आयल इंडिया लिमिटेड 1959
6. राष्ट्रीय भवन निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड 1960
7. भारतीय नौवहन निगम 1961
8. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965
9. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969
10. नेशनल अल्युमिनियम कंपनी 1981
11. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982
12. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986
13. पावर फाइनेंस कारपोरेशन 1986
14. कंटेनर कारपोरेशन निगम लिमिटेड 1988

उपरोक्त के अलावा भारत में 76 मिनिरत्न कंपनियां है ।

भारतीय औद्योगिक विकास के लिए वर्तमान में किए जा रहे प्रयास

<u>मेक इन इंडिया:</u> देश के औद्योगिक विकास वैश्विक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया । इसके अंतर्गत नए अविष्कारों एवं नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी घरेलू कंपनियों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है । इसका संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा । मेक इन इंडिया के अंतर्गत 'एक निवेश भारत' का गठन किया गया है जो विदेशी निवेशकों को नियामक व नीति संबंधी जानकारी देगा।

सन्दर्भ:भारत का भूगोल: बौद्धिक प्रकाशन, एस के ओझा, भारत का भूगोल: कॉसमॉस पब्लिकेशन, महेश बर्णवाल

****